

UPSC-CSE 2027/28

DAILY CURRENT AFFAIRS



ONE STOP SOLUTION

By **Faiyaz Sir**



The Indian
EXPRESS



THE HINDU



PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय



COMPETE
COVERAGE



EXAM
FOCUSED



ANALYSIS
MADE EASY



STATIC + CURRENT
INTEGRATION



STAY AHEAD
STAY PREPARED



बदल जाओ **वक्त** के साथ
या फिर वक्त बदलना सीखो,

मजबूरियों को मत कोसो,
हर हाल में **चलना सीखो!**

— Dr. Faiyaz Sir

- ✓ Focus
- ✓ Consistency
- ✓ Progress
- ✓ UPSC



आज क्या पढ़ेंगे?

- Steel Sector ✓
- India – Nordic Summit ✓
- महत्वपूर्ण तथ्य ✓

Scenarios
L1/1/1/1

P113

↳ Geopolitical
+ I.R.

↳



पत्र सूचना कार्यालय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार



हमारे बारे में

प्रेस विज्ञप्ति

गैलरी

अनुसंधान इकाई

मीडिया सुविधाएं

आर्काइव

तथ्यों की जांच

होम / सभी विश्लेषक / Explainer Details



Industries

भारतीय स्टील क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर

समग्र स्टील मूल्य श्रृंखला में घरेलू क्षमताओं में आई मजबूती

PIB



- भारत का स्टील क्षेत्र एक महत्वपूर्ण “सनराइज सेक्टर” है, जिसमें तेज और लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2018 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना, और आज भी इस स्थान पर काबिज है।
- घरेलू खपत बढ़ी है और यह पिछले 12 वर्षों में दोगुने से भी अधिक हो गई है। मांग बढ़ने के साथ निर्यात में वृद्धि हुई है और आयात में कमी आई है, जिससे देश की आत्मनिर्भरता मजबूत हुई है।
- इस विकास को समर्थन देने के लिए सरकार ने कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित की और उत्पादन लागत को कम किया। साथ ही, भारतीय स्टील उत्पादकों के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंच को भी बेहतर बनाया गया।
- पीएलआई योजना के अंतर्गत 23,022 करोड़ रुपये के निवेश से विशेष स्टील (स्पेशलिटी स्टील) के उत्पादन को बढ़ावा मिला और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। इससे 24 लाख टन उत्पादन हुआ और 13,000 से अधिक नए रोजगार सृजित हुए।]
- भारत ने अपनी राष्ट्रीय स्टील नीति में निर्धारित उत्पादन लक्ष्य का लगभग 66% हासिल कर लिया है।
- भारत स्टील क्षेत्र को डीकार्बनाइज करते हुए 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी क्रम में ग्रीन स्टील को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करते हुए कार्बन उत्सर्जन घटाना।



स्टील क्षेत्र में गति

- भारत का स्टील क्षेत्र राष्ट्र की विकास यात्रा की रीढ़ है। इस क्षेत्र में भारत लगातार आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत होता जा रहा है। भारत 2018 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बना और तब से यह दूसरी पोजीशन पर कायम हो कच्चे स्टील के वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 2014 में 5.2% थी जो 2024 में बढ़कर 7.9% हो गई। स्टील उत्पादन में यह वृद्धि भारत को एक मजबूत और तेजी से उभरते वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है।
- विश्व स्टील संघ के अनुसार, भारत तैयार (फिनिश) स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है देश में फिनिश स्टील की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह 2014-15 में 77 मिलियन टन से बढ़कर 2025-26 में 163.7 मिलियन टन हो गई है। यह वृद्धि देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास और बढ़ते शहरीकरण को दर्शाती है। साथ ही, यह मजबूत विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र और घरेलू मांग में लगातार वृद्धि से भी प्रेरित है। कुल मिलाकर, ये सभी रुझान इस बात को दर्शाते हैं कि भारत का स्टील क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है और देश के औद्योगिक विकास तथा आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

- भारत आत्मनिर्भरता के अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिए विदेशी स्रोतों पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। एक मजबूत घरेलू स्टील पारिस्थितिकी तंत्र नए व्यावसायिक अवसर पैदा करेगा, औद्योगिक विकास को गति देगा और देश के बुनियादी ढांचा विकास को समर्थन देगा। इसी दिशा में, भारत 2047 तक 500 मिलियन टन स्टील उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। साथ ही, 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्टील क्षेत्र से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में कमी पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

स्टील क्षेत्र का मजबूत प्रदर्शन

- दुनिया में इंजीनियरिंग और निर्माण सामग्री के रूप में सबसे अधिक उपयोग स्टील का होता है, यही कारण है कि स्टील को भारत का प्रमुख 'सनराइज सेक्टर' कहा गया। यह घरेलू खपत और औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- भारत में स्टील उत्पादन लगातार मजबूत और स्थिर गति से बढ़ रहा है। मार्च 2026 में स्टील उत्पादन, मार्च 2025 की तुलना में 2.2% बढ़ा। वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल सूचकांक में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 9.1% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। यह बढ़ोतरी उत्पादन क्षमता और मांग दोनों में मजबूती को दर्शाती है।

निर्देशः
2047
2070
घरेलू मांग

लोहा > कार्बन > मैंगनीज

- स्टील एक मिश्रधातु (एलॉय) है, जो मुख्य रूप से लोहा, कार्बन (2% से कम) और मैंगनीज (लगभग 1%) से मिलकर बनती है। इसके साथ ही इसमें थोड़ी मात्रा में सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन भी शामिल होते हैं। स्टील क्षेत्र के लिए स्टील और आयरन के विभिन्न रूप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं
- कच्चा स्टील - तरल स्टील के ठोस होने पर बनने वाला पहला ठोस स्टील उत्पाद।
- तैयार स्टील - अर्ध-तैयार स्टील के हॉट रोलिंग/फोर्जिंग के बाद तैयार होने वाला उत्पाद।
- हॉट मेटल, पिग आयरन स्पोंज स्टील - स्टील के प्रमुख स्वरूप स्टील उद्योग जगत के भीतर विभिन्न महत्वपूर्ण प्रकार के स्टील का निर्माण करते हैं।

कच्चा (कच्चा) स्टील

- कच्चा स्टील अन्य स्टील उत्पादों के लिए एक मूल कच्चा माल होता है। इसके उत्पादन में वृद्धि में तेजी आई और वर्ष 2004-05 में जहां 43.44 मिलियन टन उत्पादन था वह 2014-15 में बढ़कर 88.98 मिलियन टन और 2025-26 में 168.4 मिलियन टन तक पहुंच गया। यह भारत की मजबूती और वैश्विक स्टील क्षेत्र में इसके लगातार विस्तार को दर्शाता है। क्रूड स्टील के उत्पादन में 2021-22 से 2025-26 के बीच लगभग 9% की वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की गई। साथ ही, वित्त वर्ष 2025-26 में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में उत्पादन में 10.7% की वृद्धि हुई है।

2004 — 2026

कच्चा स्टील (मिलियन टन में)				
	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
उत्पादन	127.2	144.3	152.2	168.4

हॉट मेटल, पिग आयरन और स्पोज आयरन

- हॉट मेटल ब्लास्ट फर्नेस में तैयार होने वाला तरल लोहा होता है। 2025-26 में अप्रैल से सितंबर के दौरान इसके उत्पादन में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 7.3% की वृद्धि दर्ज की गई। ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाला एक अन्य प्रमुख उत्पाद पिग आयरन है। इसके उत्पादन में भी अप्रैल से सितंबर 2025-26 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 6.6% की बढ़ोतरी हुई। इसी अवधि में स्पोज आयरन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और इसके उत्पादन में 9.1% की वृद्धि दर्ज की गई। स्पोज आयरन को डायरेक्ट-रिड्यूस्ड आयरन भी कहा जाता है। यह सभी आंकड़े दर्शाते हैं कि स्टील उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक और संतुलित विकास हो रहा है।

फिनिश स्टील

- फिनिश स्टील (तैयार इस्पात), आधुनिक बुनियादी ढांचे और विनिर्माण के लिए एक आधारभूत सामग्री है। इसका उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में 160.9 मिलियन टन रहा। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9.7% की वृद्धि को दर्शाता है। उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ-साथ फिनिश स्टील की खपत में भी मजबूत बनी रही। यह 163.7 मिलियन टन तक पहुंच गई, जो 7.6% की वृद्धि है। ये आंकड़े देश में लगातार बढ़ती घरेलू मांग और स्टील क्षेत्र की मजबूती को उजागर करते हैं।

स्टील व्यापार की गाथा

- भारत के स्टील व्यापार का प्रदर्शन एक मजबूत और तेजी से प्रतिस्पर्धी होते घरेलू उद्योग की कहानी कहता है। मार्च 2026 में स्टील के निर्यात में साल-दर-साल आधार पर **29.1%** की वृद्धि हुई, जबकि आयात में **9.5%** की उल्लेखनीय कमी आई। यह संकेत देता है कि देश की घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ी है और विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता कम हुई है। यह सकारात्मक बदलाव इस बात का प्रमाण है कि भारत एक विश्वसनीय वैश्विक स्टील आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहा है। साथ ही, यह देश की बढ़ती घरेलू मांग को भी पूरा करने की बेहतर क्षमता को भी दर्शाता है।
- भारत ने आयरन और स्टील अलॉय (मिश्रधातु) के प्रमुख निर्यातक के रूप में भी अपनी मजबूत पहचान स्थापित की है। स्टील और उससे जुड़े उत्पादों के बढ़ते निर्यात से विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि होती है, जिससे देश के व्यापार संतुलन में सुधार होता है। यह आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एक सशक्त और स्वावलंबी औद्योगिक तंत्र के लक्ष्य को भी समर्थन देता है।

सरकार द्वारा किए गए सुधार स्टील क्षेत्र को दे रहे संबल

- सरकार ने कच्चे माल की उपलब्धता मजबूत करने, वैश्विक बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन उपायों से उत्पादन लागत में कमी आई है, स्टील उद्योग को बढ़ावा देने को गति मिली है, और एमएसएमई तथा छोटे स्टील उत्पादकों को भी मजबूत समर्थन मिला है।
- स्टील एक **डी-रेगुलेटेड (नियंत्रण-मुक्त)** क्षेत्र है, जिसमें सरकार सीधे हस्तक्षेप करने के बजाय इसके विकास और विस्तार के लिए अनुकूल नीतिगत ढांचा तैयार करके सहयोगी भूमिका निभाती है।

स्पेशलिटी स्टील के लिए प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना

- प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना** सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र कंपनियों को उनकी बढ़ी हुई बिक्री (इन्क्रीमेंटल सेल्स) के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन (इंसेंटिव) दिया जाता है।

स्टील मंत्रालय की पीएलआई 1.0 और पीएलआई 1.1 योजना

States with Approved PLI Projects (Specialty Steel)



Source: Ministry of Steel

क्या आप जानते हैं?

(12) Steel zone

देश के प्रमुख स्टील जोन निम्न स्थानों पर स्थित हैं:
कालिंगानगर, अंगुल, राउरकेला, झारसुगुड़ा, नगरनार,
भिलाई, रायपुर, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, कोलकाता,
विशाखापट्टनम

2070 Nov - 2040

ग्रीन स्टील वह स्टील है जिसका निर्माण जीवाश्म ईंधनों के उपयोग के बिना किया जाता है। तथाकथित "ग्रीन हाइड्रोजन" एक ऐसा समाधान है जो स्टील उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायक हो सकता है।

Detail

✓ घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन

- घरेलू रूप से निर्मित आयरन एवं स्टील उत्पाद (डीएमआई एवं एसपी) नीति
- **राष्ट्रीय स्टील नीति:** राष्ट्रीय स्टील नीति 2017 का लक्ष्य वर्ष **2030-31** तक कच्चे स्टील की क्षमता को **300** मिलियन टन प्रति वर्ष और उत्पादन को **255** मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाना है। इसके अलावा, प्रति व्यक्ति फिनिश स्टील की खपत को वर्तमान 61 किलोग्राम से बढ़ाकर 158 किलोग्राम करने का लक्ष्य रखा गया है। यह नीति उच्च गुणवत्ता वाले ऑटोमोबाइल, विद्युत (इलेक्ट्रिकल) और विशेष स्टील (स्पेशलिटी स्टील) की घरेलू मांग को पूरा करने पर भी केंद्रित है। साथ ही, वर्ष **2030-31** तक कोकिंग कोल के आयात पर निर्भरता को **85%** से घटाकर **65%** करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।
- भारत ने कच्चे स्टील का उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में पहले ही **168** मिलियन टन प्रति वर्ष हासिल कर लिया है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय स्टील नीति 2017 के अंतर्गत निर्धारित कच्चे स्टील उत्पादन क्षमता का लगभग **66%** लक्ष्य पूरा हो चुका है। यह दीर्घकालिक उत्पादन क्षमता लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

✓ **पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान (अक्टूबर, 2021):** स्टील मंत्रालय ने 2,100 से अधिक कार्यरत स्टील इकाइयों का जियोलोकेशन डेटा पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया है। इसमें इन इकाइयों के उत्पाद और उनकी उत्पादन क्षमता से जुड़ी जानकारी भी शामिल है, ताकि स्टील क्षेत्र में समन्वित (कोऑर्डिनेटेड) और डेटा-आधारित लॉजिस्टिक्स योजना को बेहतर बनाया जा सके।

✓ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच

- सरकार द्वारा **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)** नीतियों में किए गए सुधारों ने एफडीआई प्रवाह बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके परिणामस्वरूप 2014 से 2024 के बीच एफडीआई प्रवाह में 2004-2014 की तुलना में **120%** की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी अवधि में विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई **इक्विटी निवेश** में भी **69%** की बढ़ोतरी हुई है।
- सरकार ने **ऑटोमैटिक रूट** के तहत **100%** एफडीआई की अनुमति देकर इस क्षेत्र को मजबूत समर्थन दिया है। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2000 से जून 2025 के बीच धातुकर्म (मेटलर्जिकल) उद्योगों में **1,60,000** करोड़ रुपये (**18.67** बिलियन अमरीकी डॉलर) का निवेश आकर्षित हुआ है।
- इसके अलावा, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ (ईयू) और अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) इस क्षेत्र के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंच को और विस्तारित करने में सहायक होंगे।

लो - कार्बन स्टील के लिए सरकारी उपाय

- लो - कार्बन स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं।
- केंद्रीय बजट 2026-27 में स्टील और अन्य उद्योगों के लिए कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सी सी यू एस) तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव रखा गया है।

प्रश्न 1. भारतीय इस्पात (Steel) क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा स्टील (Crude Steel) उत्पादक और तैयार (Finished Steel) स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है।
2. 'राष्ट्रीय इस्पात नीति (National Steel Policy)' के तहत विशेष स्टील (Speciality Steel) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना लागू की गई है।
3. ग्रीन स्टील (Green Steel) का मुख्य उद्देश्य इस्पात निर्माण प्रक्रिया में जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuels) के उपयोग को कम करके कार्बन उत्सर्जन को घटाना है।

→ भूगोल - ससाधन

→ Economy - उद्योग

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3

41-460

मुख्य परीक्षा (Mains Practice Questions)

- "भारतीय इस्पात उद्योग न केवल बुनियादी ढांचे और आर्थिक प्रगति की रीढ़ है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।" हालिया सुधारों, चुनौतियों और 'ग्रीन स्टील' (Green Steel) की दिशा में भारत के प्रयासों के आलोक में इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

(250 शब्द / 15 अंक)



पत्र सूचना कार्यालय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार



हमारे बारे में

प्रेस विज्ञप्ति

गैलरी

अनुसंधान इकाई

मीडिया सुविधाएं

आर्काइव

तथ्यों की जांच

होम / सभी विश्लेषक / Explainer Details



Global Affairs

तृतीय भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन

हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी में वृद्धि

PIB
20.10.24
11:31 AM
Lx 24-3644

- नॉर्डिक (Nordic) और स्कैंडिनेवियाई (Scandinavian) दोनों शब्द अक्सर उत्तरी यूरोप के देशों के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन ये दोनों एक नहीं हैं, इनमें भौगोलिक और सांस्कृतिक अंतर है।
- इसे आसान शब्दों में ऐसे समझें: "सभी स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्डिक हैं, लेकिन सभी नॉर्डिक देश स्कैंडिनेवियाई नहीं हैं।"
- इन दोनों के बीच का मुख्य अंतर नीचे दिया गया है:

1. स्कैंडिनेविया (Scandinavia)

- स्कैंडिनेविया एक पारंपरिक और भाषाई (Linguistic) समूह है जो मुख्य रूप से 'स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप' पर स्थित देशों से मिलकर बनता है।
- इसमें शामिल देश:
 - नॉर्वे (Norway)
 - स्वीडन (Sweden)
 - डेनमार्क (Denmark)
- विशेषता: इन तीनों देशों की भाषाएँ (नॉरवेजियन, स्वीडिश और डेनिश) आपस में बहुत मिलती-जुलती हैं (North Germanic languages) और इनका इतिहास व संस्कृति बहुत हद तक एक जैसी है। (कभी-कभी इसमें फिनलैंड और आइसलैंड को भी सांस्कृतिक समानता के कारण जोड़ लिया जाता है, लेकिन भौगोलिक रूप से वे इसमें नहीं आते)।

2. नॉर्डिक देश (Nordic Countries)

- नॉर्डिक एक बड़ा और व्यापक (Broad) भौगोलिक और राजनीतिक समूह है। इसमें वे सभी देश शामिल हैं जो उत्तरी यूरोप और उत्तर अटलांटिक क्षेत्र में आते हैं और जिनका आपस में गहरा राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग है (जिसे 'नॉर्डिक काउंसिल' के तहत मैनेज किया जाता है)।
- इसमें शामिल देश:
 - नॉर्वे (Norway)
 - स्वीडन (Sweden)
 - डेनमार्क (Denmark)
 - फिनलैंड (Finland)
 - आइसलैंड (Iceland)
 - (साथ ही इनके अधीन आने वाले क्षेत्र जैसे ग्रीनलैंड, फरो द्वीप समूह और एलैंड द्वीप भी इसमें शामिल हैं)।
- विशेषता: फिनलैंड और आइसलैंड भूगोल और भाषा के मामले में स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं हैं (फिनिश भाषा यूरालिक परिवार से है, जो इंडो-इरियन/जर्मैनिक नहीं है), लेकिन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों (जैसे उच्च कल्याणकारी राज्य / High Welfare State मॉडल) की वजह से इन्हें नॉर्डिक कहा जाता है।

- भारत और नॉर्डिक देशों से 2018 में पहले भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान एक बहुआयामी साझेदारी आरंभ की थी। साझेदारी नवाचार, हरित प्रौद्योगिकियों, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास पर केंद्रित है।
- इसका उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास में सहायता करना, सतत विकास मार्गों को बढ़ावा देना, कौशल और प्रतिभा विकास को सुदृढ़ करना और एक जीवंत नवाचार इको-सिस्टम को बढ़ावा देना है।
- भारत नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई पहलों में सहयोग के माध्यम से नॉर्डिक विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का भी लाभ उठा सकता है।
- 19 मई 2026 को ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ने इस रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाया।
- शिखर सम्मेलन ने व्यापार, निवेश, डिजिटल नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत किया। दोनों पक्षों ने सामुद्रिक अर्थव्यवस्था, समुद्री सहयोग, एसटीईएम अनुसंधान, गतिशील आपूर्ति श्रृंखला और रक्षा साझेदारी में सहयोग का भी विस्तार किया।
- आर्थिक साझेदारी के अतिरिक्त, भारत कूटनीति के सॉफ्ट पावर टूल के माध्यम से भी नॉर्डिक देशों से जुड़ा है।

भारत की आर्कटिक नीति

- नॉर्डिक देशों के साथ गठबंधन भारत की आर्कटिक नीति का एक अनिवार्य घटक है। आर्कटिक में जलवायु परिवर्तन, विशेष रूप से आर्कटिक बर्फ का पिघलना, मानसून सहित मौसम की स्थिति और वर्षा के पैटर्न को बेहद प्रभावित कर सकता है। ये परिवर्तन भारत की आर्थिक, खाद्य और जल सुरक्षा और 1300 से अधिक द्वीप क्षेत्रों और समुद्री सुविधाओं की स्थिरता के लिए अत्यधिक विघटनकारी हो सकते हैं।
- भारत की आर्कटिक नीति जिसका शीर्षक 'भारत और आर्कटिक: सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण' है, छह स्तंभों के इर्द-गिर्द संरचित है: भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग का सुदृढ़ीकरण, जलवायु और पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक और मानव विकास, परिवहन और कनेक्टिविटी, शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आर्कटिक क्षेत्र में राष्ट्रीय क्षमता निर्माण।

नॉर्डिक देशों के साथ भारत का बढ़ता सहयोग

- नॉर्डिक क्षेत्र के साथ भारत का जुड़ाव पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी में विकसित हो गया है। हरित विकास, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, नवाचार और सतत विकास में साझा प्राथमिकताएं इस परिवर्तन को आगे बढ़ा रही हैं। नॉर्डिक देश उन्नत तकनीकी विशेषज्ञता लाते हैं, जबकि भारत परिमाण, बाजार, प्रतिभा और विनिर्माण क्षमताएं प्रदान करता है। साथ में यह साझेदारी भारत के हरित परिवर्तन, डिजिटल विस्तार, आर्कटिक जुड़ाव और गतिशील आर्थिक विकास रणनीति के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभर रही है।

डेनमार्क:

- भारत और डेनमार्क के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 2025 में 2.05 बिलियन डॉलर था।
- उसी वर्ष डेनमार्क को भारत का निर्यात 1.06 बिलियन डॉलर और आयात 0.98 बिलियन डॉलर था। सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार 4.25 बिलियन डॉलर तक पहुंचा; 2025 में भारत से निर्यात 1.9 बिलियन डॉलर और आयात 2.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
- डेनमार्क में भारतीय निवेश का कुल मूल्य लगभग 560 मिलियन डॉलर है।
- डेनमार्क में आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा और इंजीनियरिंग सहित विभिन्न सेक्टरों में लगभग 40 भारतीय कंपनियां विद्यमान हैं और डेनमार्क की लगभग 200 कंपनियों ने भारत में शिपिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और स्मार्ट शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश किया है।
- 2024 तक डेनमार्क से भारत में संचयी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह 1.413 बिलियन डॉलर था।
- भारत और डेनमार्क ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (2022) और "भारत और डेनमार्क से चांदी के खजाने" प्रदर्शनी जैसी पहलों के माध्यम से सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत किया।
- आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान *प्रमुख सांस्कृतिक लोक संपर्क कार्यक्रमों* में ध्वजारोहण, त्योहार, स्कूल कार्यक्रम, खेल कार्यशालाएं और डेनमार्क भर में व्यापक प्रवासी भागीदारी शामिल हैं, जो सॉफ्ट पावर दृष्टिकोण को दर्शाती हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डेनमार्क के शहरों में व्यापक रूप से मनाया जाता है, जिसमें व्यापक स्तर पर भागीदारी होती है और कोपेनहेगन में "सभी के लिए योग" जैसे प्रमुख कार्यक्रम होते हैं।
- डेनमार्क में लगभग 21,000 का भारतीय समुदाय सक्रिय रूप से सभी व्यवसायों में योगदान देता है। आरहूस में आरहूस यूनिवर्सिटी के पास गांधी प्लेन (गांधी पार्क), इंडियाकाज (भारत के नाम पर सड़क) और नेहरू रोड जैसे सार्वजनिक स्थान दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत लोगों और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक हैं।
- 2026 में भारत और डेनमार्क के नेताओं ने गतिशीलता, साझेदारी को मजबूत करने और लोगों के बीच परस्पर आदान-प्रदान का विस्तार करने पर चर्चा की।

फ़िनलैंड:

- 2024-25 में फिनलैंड के साथ वस्तुओं में द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा 1.017 बिलियन डॉलर थी। उसी वर्ष फिनलैंड को भारत का निर्यात 356.37 मिलियन डॉलर और आयात 660.70 मिलियन डॉलर था।
- 2025 में सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार 1.9 बिलियन डॉलर था। भारत से फिनलैंड में निवेश प्रवाह 2 बिलियन डॉलर से अधिक है, जो कई महत्वपूर्ण अधिग्रहणों और साझेदारियों से प्रेरित है। भारत में 100 से अधिक फिनलैंड की कंपनियों का परिचालन है। भारत में फिनलैंड का निवेश बढ़कर 4 बिलियन डॉलर हो गया है।
- फिनलैंड में भारतीय संस्कृति की मजबूत उपस्थिती है, योग केंद्र, प्रदर्शन कला, भारतीय नृत्य स्कूल और सांस्कृतिक संघ संगीत, नृत्य और त्योहारों में नियमित कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं, जो भारतीय दूतावास द्वारा समर्थित हैं। दूतावास 'तेर्वे-नमस्ते' श्रृंखला के तहत भारतीय छात्रों के साथ नियमित रूप से बैठक आयोजित करता है।
- फिनलैंड में भारतीय समुदाय लगभग 33,000 है, जिसकी आईटी क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति है और लगभग 2,400 छात्र उच्च शिक्षा से जुड़े हैं।
- पर्यटन और यात्रा संपर्क बढ़ रहे हैं, फिनलैंड के पर्यटक गोवा, केरल और स्वर्ण मंदिर जैसे गंतव्यों की यात्रा कर रहे हैं, जो ई-वीजा सुविधाओं और हेलसिंकी एवं नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ानों द्वारा समर्थित हैं।
- 2026 में भारत और फिनलैंड ने अपनी प्रौद्योगिकी और नवाचार इको-सिस्टम में भारतीय पेशेवरों के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया।

आइसलैंड:

- आइसलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा 2024-25 में 77.06 मिलियन डॉलर थी।
- उसी वर्ष आइसलैंड को भारत का निर्यात 66.01 मिलियन डॉलर और आयात 11.05 मिलियन डॉलर था।
- भारतीय संस्कृति विशेष रूप से योग, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, पेंटिंग, फिल्मों और भोजन में आइसलैंड में लोकप्रिय है। आइसलैंड में करीब 600 भारतीय नागरिक हैं।
- 2026 में भारत और आइसलैंड ने सहयोग की समीक्षा की और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने, सांस्कृतिक और पर्यटन आदान-प्रदान का विस्तार करने और आर्कटिक अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।



नॉर्वे:

- भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में 1.05 बिलियन डॉलर था।
- भारत ने इसी अवधि में 630 मिलियन डॉलर के सामान का निर्यात किया और 420 मिलियन डॉलर के सामान का आयात किया।
- सेवाओं में व्यापार करीब 1 बिलियन डॉलर का रहा है।
- नॉर्वे के गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल (जीपीएफजी) ने भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 28 बिलियन डॉलर (दिसंबर 2025 तक) का निवेश किया है
- इसके अलावा, अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 के दौरान नॉर्वे से एफडीआई प्रवाह 764 मिलियन डॉलर था।
- भारत और नॉर्वे लगभग 30,000 लोगों के भारतीय समुदाय के माध्यम से लोगों से लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध साझा करते हैं।
- भारतीय छात्र, शोधकर्ता और 40 से अधिक भारतीय संघ नॉर्वे में सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं।
- टर्बैडजेन और ओस्लो कलर फेस्टिवल जैसे आयोजन नॉर्वे में भारतीय संस्कृति और सॉफ्ट पावर के बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हैं।



स्वीडन:

- भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 6.96 बिलियन डॉलर था।
- अप्रैल 2000 से दिसंबर 2024 तक स्वीडन से संचयी एफडीआई इक्विटी प्रवाह 2.596 बिलियन डॉलर था।
- भारत में स्वीडन की लगभग 280 कंपनियों की व्यावसायिक उपस्थिति है, जबकि 2024 में व्यावसायिक उपस्थिति वाली भारतीय कंपनियों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है।
- भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य, योग, आयुर्वेद, भारतीय त्योहारों और सिनेमा जैसी भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को स्वीडन में व्यापक रूप से सराहा जाता है।
- स्वीडन के शहरों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव भारत के बढ़ते सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है।
- वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव नमस्ते स्टॉकहोम हजारों आगंतुकों को आकर्षित करता है और भारतीय कला और अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।
- भारतीय और स्वीडन के विश्वविद्यालयों के बीच सक्रिय भागीदारी है। उप्साला में इंडोलॉजी का अध्ययन लगभग 200 साल पुराना है, जो भारतीय सभ्यता के साथ विद्वानों के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है।

- खेल और सिनेमा भी द्विपक्षीय संबंधों में योगदान करते हैं। 2021 में, भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने स्वीडन का दौरा किया, भारतीय डेविस कप टीम ने 2024 में दौरा किया, स्वीडिश फिल्म निर्माता लेवन अकिन ने 2024 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी मैडल प्राप्त किया।
- लगभग 88,000 लोगों का भारतीय प्रवासी समूह भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में मदद करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाता है।
- भारत और नॉर्डिक देश नवाचार, स्थिरता और रणनीतिक विश्वास के आकार की साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। यह संबंध अब स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन, गतिशील आपूर्ति श्रृंखला, अनुसंधान और समुद्री सहयोग तक फैला हुआ है। भारत के परिमाण और प्रतिभा के साथ मिलकर नॉर्डिक विशेषज्ञता दीर्घकालिक सहयोग के लिए मजबूत अवसर पैदा करती है। बढ़ते संस्थागत, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ यह साझेदारी धीरे-धीरे समावेशी, प्रौद्योगिकी-संचालित और टिकाऊ वैश्विक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल के रूप में उभर रही है।

तीसरा नॉर्डिक शिखर सम्मेलन: दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की दिशा में भविष्य के कदम

- तीसरे नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच चर्चा हुई। पिछले दशक के दौरान द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह में चार गुना वृद्धि, निवेश प्रवाह में लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि और भारत के आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव की सराहना करते हुए, भारत और नॉर्डिक देश अपने संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमत हुए हैं। इस पहल के तहत, भारत की निम्नलिखित योजना है:
- भूतापीय ऊर्जा और मत्स्य पालन में आइसलैंड के साथ सहयोग करना,
- समुद्रीय अर्थव्यवस्था और आर्कटिक सहयोग में नॉर्वे के साथ भागीदारी करना और
- सामुद्रिक और स्थिरता क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ जुड़ना।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims Practice Questions)

- प्रश्न 1. भारत-नॉर्डिक संबंधों और तृतीय भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
 1. पहला भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था।
 2. तृतीय भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन 19 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किया गया।
 3. इस सम्मेलन का मुख्य केंद्र हरित प्रौद्योगिकियों (Green Technologies), नवाचार (Innovation), समुद्री अर्थव्यवस्था (Blue Economy) और जलवायु कार्रवाई (Climate Action) पर आधारित था।

2018
दूसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन
2026

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3

41-43

मुख्य परीक्षा (Mains Practice Questions)

- "तृतीय भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ने भारत और नॉर्डिक देशों के बीच साझेदारी को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार की दिशा में नए आयाम दिए हैं" भारत के सतत विकास (Sustainable Development) और आर्कटिक क्षेत्र में उसके सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस साझेदारी के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- (250 शब्द / 15 अंक)

Trains cut, Internet down: Delhi turns a fortress ahead of protest

Police deny permission for the CJP protest at Jantar Mantar; Home Ministry directs States, Union Territories to prevent protesters from entering capital; around 13,000 additional Central security personnel deployed amid heightened security

Vijeta Singh
NEW DELHI

The Delhi Police on Friday denied permission to the Cockroach Janta Party (CJP) to hold its proposed protest at Jantar Mantar on Saturday, citing alleged violations of conditions agreed upon for an earlier demonstration, even as authorities rolled out an extensive security plan across the national capital.

Despite the denial of permission, the CJP released a poster that says "Final Call To Save Democracy", asking its supporters to reach Jantar Mantar at 10 a.m. on October 10 as they look to go ahead with the protest demanding the resignation of Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar and the rollback of the special intensive revision (SIR) of electoral rolls.

Authorities have taken several measures ahead of the protest, including Internet curbs in parts of Delhi, the shutting down of markets and metro stations, and the cancelling of dozens of trains bound for the capital.

The Union Ministry of Home Affairs (MHA) directed all States and Union Territories (U.T.s) to coordinate with the Delhi Police and take preventive measures to stop the movement of protesters towards Delhi. In a communication sent to Chief Secretaries and Directors General of Police (DGP), Union Home Secretary Govind Mohan drew attention to the "grave law-and-order and public-order implications" arising from the proposed protest.

The letter noted that the Delhi Police had categorically rejected the CJP's request to hold the gathering. The communication further said the CJP and supporting organisations



Under wraps: Glass panels at a Metro station are covered ahead of a Cockroach Janta Party protest near Jantar Mantar in New Delhi on Saturday. (Photo: Sreelaxa Kuper)

had a "documented history of non-compliance with lawful directions" during previous mobilisations, adding that earlier protests involving participants travelling from different States had resulted in significant disruption to public order and damage to public property, the letter, seen by The Hindu, said.

'Preventive measures'

The letter cited intelligence inputs as indicating that the CJP and its supporters intended to defy statutory restrictions and attempt entry into Delhi from various States and U.T.s. "To pre-empt any breach of public tranquillity and to safeguard critical infrastructure," the Home Ministry directed States to "immediately operationalise preventive measures in coordination with the Delhi Police and within the framework of law".

The Ministry emphasised continuous, real-time intelligence-sharing among State intelligence agencies, transit authorities and the Delhi Police to ensure coordinated action.

Around 6,000 additional security personnel – 40 companies of the Indo-Tibetan Border Police (ITBP) and 20 companies of Sashastra Seema Bal (SSB), the primary border guarding forces along the border with China and Nepal, respectively – were deployed in Delhi for "law-and-order duty" on the instructions of the Union Home Ministry.

This deployment is in addition to the 7,000 Central Reserve Police Force (CRPF) personnel pulled from Chhattisgarh and West Bengal, as well as personnel of the Delhi Police.

Joint Commissioner of Police (New Delhi Range) Nupur Prasad said the organisers had failed to comply with undertakings given during a previous protest. "Because of not following the conditions as part of undertaking during the past protest, this time, the permission has been denied," she said.

Police officials also noted that the request for permission had been submitted at short notice. According to them, CJP

Repeal all State polls: INDIA bloc

Sobhana K. Nair
NEW DELHI

The INDIA bloc on Friday urged President Droupadi Murmu to "repeal" all Assembly polls held over the last two years, saying they have proof of vote theft. Sources said, Rahul Gandhi, before their meeting with Ms. Murmu, said the Centre is "rattled" and that if the Opposition continues its campaign, the Centre may fall.

FULL REPORT ON
PAGE 4

'Blanket ban on transit is over-reaching'

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Supreme Court on Friday found the Delhi Police's move to shut down free movement to and within the national capital ahead of the protests on Saturday "over-reaching". The top court told the Union government and the Delhi Police that a "distinction exists between total 'prohibition' and the 'regulation' of Metro and other train movements".

A three-judge Bench drew an assurance from Solicitor-General Tushar Mehta that he would "impress upon the authorities to reassess the travel prohibitions".

Choosing gentle persuasion over a legal showdown in the courtroom, the court pressed for the

RELATED REPORTS ON
PAGE 3 & 4

FULL REPORT ON
PAGE 4

Blanket transit ban in Delhi over-reaching: SC

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Supreme Court on Friday found the Delhi Police's move to shut down free movement to and within the national capital ahead of the protests on Saturday "over-reaching". The court told the Union government and the Delhi Police that a "distinction exists between total 'prohibition' and the 'regulation' of Metro and other train movements".

A three-judge Bench drew an assurance from Solicitor-General Tushar Mehta that he would "impress upon the authorities to reassess the travel prohibitions".

Choosing gentle persuasion over a legal showdown in the courtroom, the court pressed for the



The Central Secretariat Metro station closed in view of a protest against CEC Gyanesh Kumar in Delhi on October 2. ANI

operation of Metro and other rail services in the national capital in a "suitable and regulated manner".

"We clarify that although there shall be no outright prohibition on the movement of Metro trains, a prudent decision may be

made to permit the operation of Metro trains and other rail services in a suitable and regulated manner. Such a decision should be widely publicised to prevent further inconvenience," the court directed in a four-page order.

The Bench, headed by

Chief Justice of India Surya Kant, did not expand on what it exactly meant by a "suitable and regulated manner", but indicated the restrictions must be proportionate.

The court even suggested that the government ought to find an open, spacious site for protesters to "peacefully and lawfully" protest in the capital. The protest is expected to happen at Jantar Mantar, the designated site for voicing dissent in the national capital.

However, the court remarked that central Delhi was usually cramped with no washroom, medical and drinking water facilities. The government found the court's proposal for an alternative protest site welcome, and promptly

agreed to take a decision.

The hearing began with an impromptu oral mentioning by senior lawyers before the Bench. They urged the court to step in, saying the capital has been "heavily barricaded", making free movement virtually impossible.

A writ petition filed by Communist Party of India (Marxist) general secretary M.A. Baby said express trains to Delhi, from as far away as Keralam, were cancelled on Friday.

Justice Bagchi stressed that freedom of association was indeed a fundamental right, but it had to be verified whether permission for the protest had been obtained. The judge said that if not, the protest may prove to be illegal.

YouTube Homework

➤ Article - 19

10 October 2026
यु-307 दिवसी
L'comg
यु-11
यु-11

महत्वपूर्ण तथ्य



- दिल्ली में आज (10 अक्टूबर 2026) कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और अन्य समूहों के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने कई पाबंदियां लगाई हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया है। [

1. सरकार और पुलिस द्वारा लगाई गई पाबंदियां

- मेट्रो और ट्रेन सेवाएं: दिल्ली में कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश/निकास द्वार बंद करने और नई दिल्ली व हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आने वाली ट्रेनों पर रोक या पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया था।
- सड़कों पर बैरिकेडिंग और जंतर-मंतर पर रोक: शनिवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की मांग खारिज कर दी गई। पुलिस का कहना था कि यह आवेदन बहुत कम समय (देरी से) दिया गया था, जबकि नियम के अनुसार कम से कम 10 दिन पहले अनुमति मांगनी चाहिए थी और पिछली बार के प्रदर्शनों में कानून के उल्लंघन का रिकॉर्ड भी रहा है।

2. सुप्रीम कोर्ट का रुख और टिप्पणी

CSL

- "मक्खी मारने के लिए हथौड़ा नहीं" (Over-reaching): मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और पीठ ने कहा कि सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके नाम पर पूरे शहर का जनजीवन ठप नहीं किया जा सकता।
- विनियमन (Regulation) बनाम पूर्ण प्रतिबंध (Prohibition): अदालत ने स्पष्ट किया कि मेट्रो या ट्रेनों की आवृत्ति (frequency) कम करना नियमन हो सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम को पूरी तरह बंद करना 'प्रतिबंध' है। कोर्ट ने अधिकारियों को इस पर पुनर्विचार करने और सामान्य आवाजाही सुचारू रखने के निर्देश दिए।
- प्रदर्शन के अधिकार का समर्थन: कोर्ट ने माना कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है, लेकिन यह भी कहा कि तय नियमों और समय पर अनुमति लेना जरूरी है।

महत्वपूर्ण तथ्य



3. क्या विरोध प्रदर्शन करना एक अधिकार है? (संवैधानिक प्रावधान)

- भारत के संविधान के तहत विरोध प्रदर्शन करना और इकट्ठा होना नागरिकों का अधिकार है:
- अनुच्छेद 19(1)(b): भारत के सभी नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्वक (Peacefully) एकत्र होने और सभा करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 19(1)(a): वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression) का अधिकार, जिसके तहत सरकार की नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध जताना भी शामिल है।
- अनुच्छेद 19(1)(c): संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार।

निर्दिष्ट

4. इन अधिकारों पर किन शर्तों में पाबंदियां (Limitations) लगाई जा सकती हैं?

- संविधान के अनुच्छेद 19(3) के तहत शांतिपूर्ण एकत्र होने के अधिकार पर कुछ उचित प्रतिबंध (Reasonable Restrictions) लगाए जा सकते हैं:
- भारत की संप्रभुता और अखंडता: यदि प्रदर्शन से देश की एकता या सुरक्षा को खतरा हो।
- लोक व्यवस्था (Public Order): यदि प्रदर्शन से इलाके की शांति भंग होने, दंगे या भारी हिंसा फैलने का अंदेशा हो।
- शांति और नैतिकता: यातायात, अस्पतालों, स्कूलों या आम जनता के दैनिक जीवन में अत्यधिक और अनावश्यक बाधा न पहुंचे।
- पूर्व अनुमति और नियम: प्रशासन द्वारा तय समयावधि (जैसे 10 दिन पहले सूचना देना) और स्थान के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, बिना अनुमति के प्रदर्शन गैर-कानूनी माना जा सकता है।

Govt. is against monopolies: Minister on Musk's remarks

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Union Communications Minister Jyotiraditya Scindia said on Friday that India "does not allow a monopoly in any sector", referring to SpaceX chief executive officer Elon Musk's allegations that "oligarchs" were blocking Starlink service's availability in India. Starlink is a satellite Internet service operated by SpaceX.

"For us in the Department of Telecommunications [DoT], we are technology agnostic," Mr. Scindia said. "Our job is to be able to provide the bouquet of services to every single customer. It is for



Jyotiraditya Scindia

the customer to choose, in a free market, which service he or she prefers."

Mr. Scindia reiterated the DoT's statement asserting that all three satellite Internet licence applicants, Starlink, Jio and Bharti-backed OneWeb, were at the same stage. "Once the revenue charges system is finalised – once each one of these parties,

party A, B and C, all three individually, based on their achievement of milestones with regard to security concerns and prerequisites, have fulfilled the requirements – then obviously they can start operations," he said.

On why the revenue charge system – the key step before Starlink can operate on top of the security clearance – was delayed, Mr. Scindia said, "You say something in a snap, and DoT quickly announces it, and then six months later we will be asked why we announced it in such a hurry."

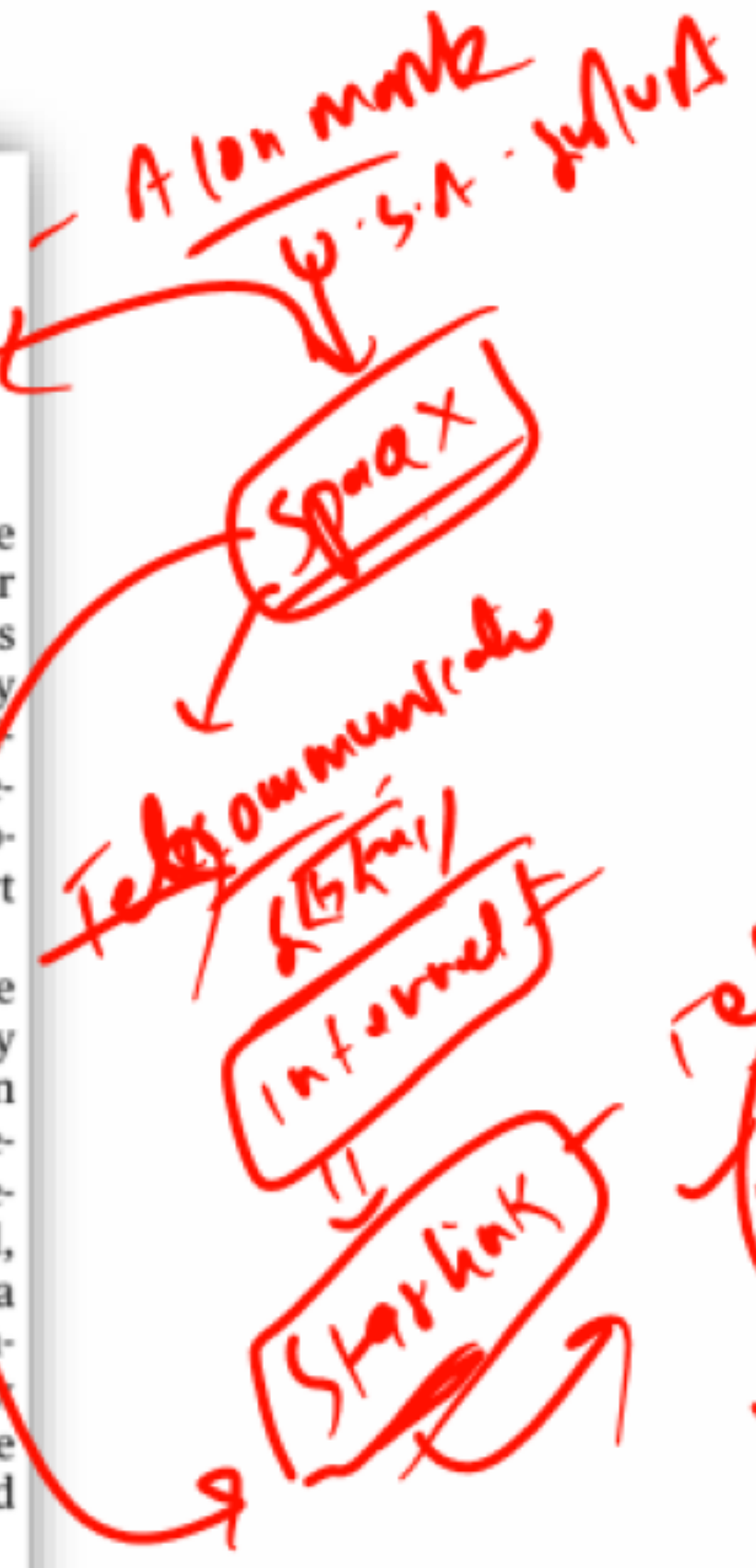
RELATED REPORTS ON
» PAGE 3

YouTube Homework

SpaceX

Monopoly
पारितोषिक

Jio Monopoly



महत्वपूर्ण तथ्य

SC rejects A.P. plea to restore 34% BC quota in local bodies

Court says data from a unified family survey are insufficient to justify the enhanced reservation; State argues the 2026 quota exercise was based on a fresh survey and a dedicated panel's findings

Aaratrika Bhaumik
NEW DELHI

The Supreme Court on Friday dismissed the Andhra Pradesh government's appeal against a High Court ruling that struck down its decision to restore 34% reservation for Backward Classes (BC) in local bodies. The court upheld the October 1 verdict that the State had failed to produce the empirical data necessary to justify breaching the 50% reservation ceiling.

Senior advocate Mukul Rohatgi contended before a Bench of Justices Dipan- kar Datta and Sheel Nagu that the State's decision

You show us how this data can be considered. This is a unified family survey. Under what law is this being made? Very reasonable approach by the High Court
SUPREME COURT



TDP to give 34% seats to BCs in local polls: Naidu

Reacting to the SC verdict, A.P. CM N. Chandrababu Naidu said the TDP would continue to ensure representation for BCs by allotting 34% seats in the local body polls.

was supported by demographic data and other empirical material, but the High Court had erroneously concluded that it fell short of the requirements previously laid down by the top court for breaching the 50% reservation cap.

The Bench observed that figures drawn from a

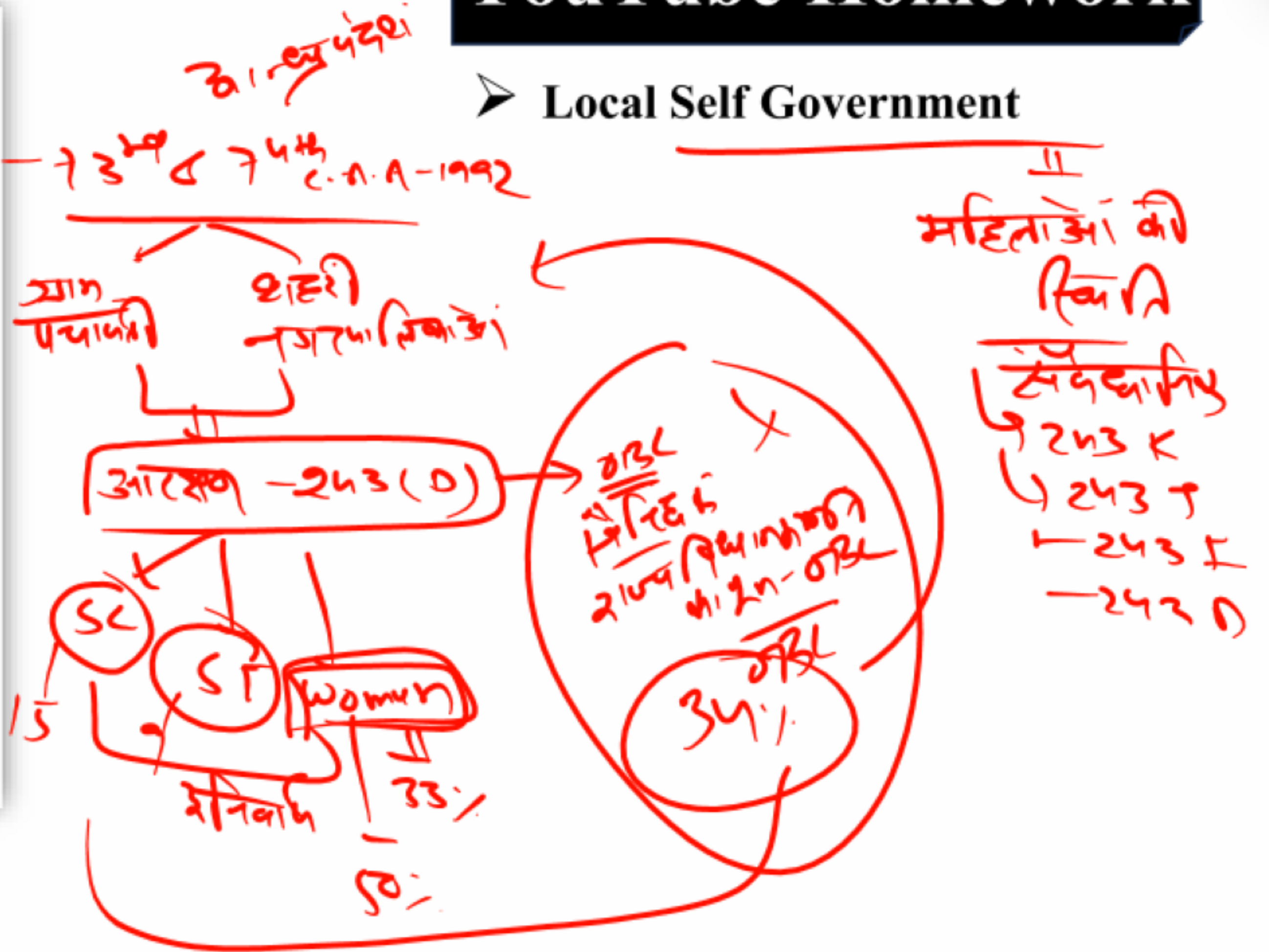
unified family survey were insufficient to justify the enhanced quota in the absence of a specific empirical assessment of backwardness and representation in local bodies. "You show us how this data can be considered. This is a unified family survey. Under what

law is this being made? Very reasonable approach by the High Court," the Bench remarked while dismissing the plea.

The State argued the 2026 quota exercise was based on a fresh survey, local-body data and a dedicated commission's findings.

YouTube Homework

➤ Local Self Government



महत्वपूर्ण तथ्य

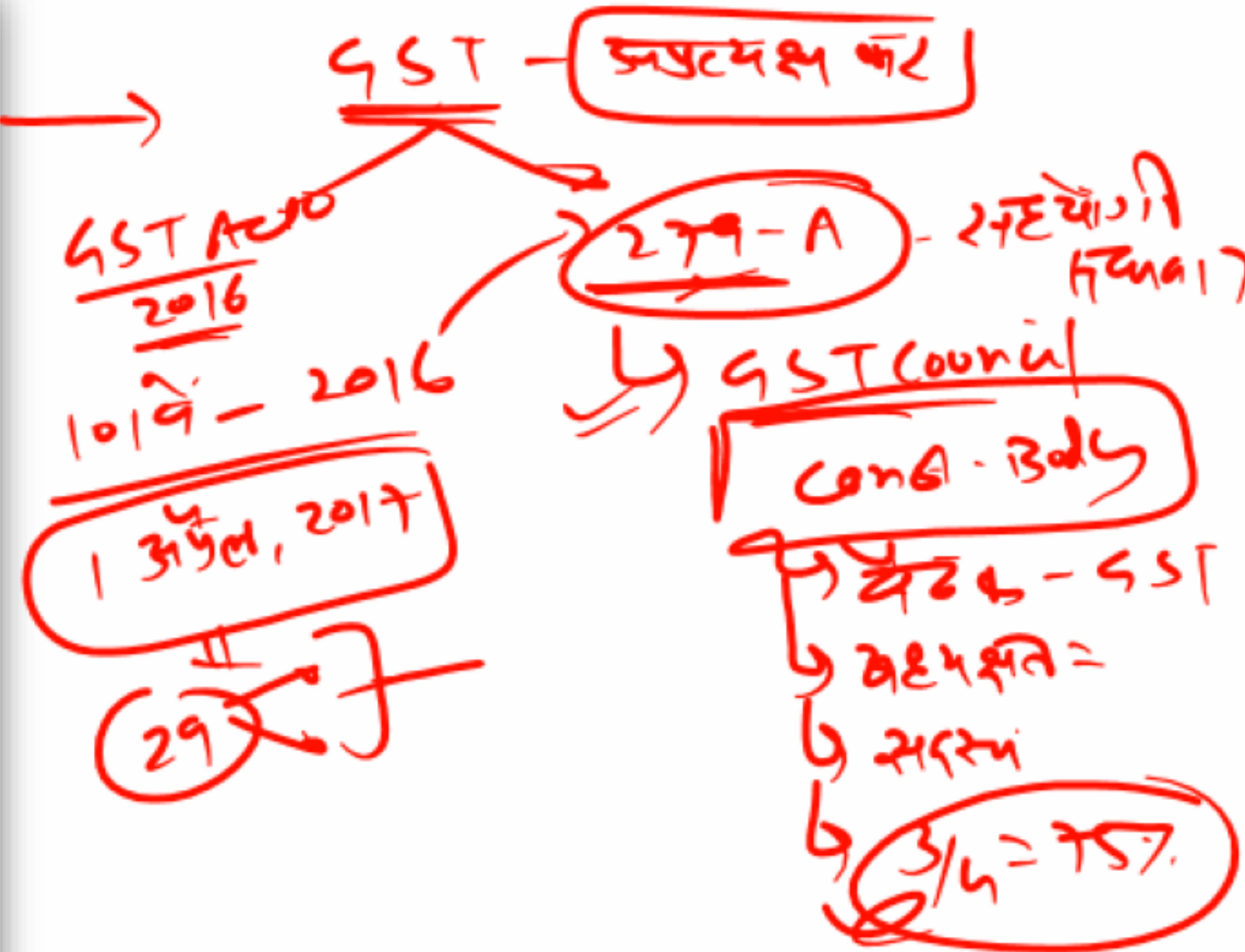


Delivery completed

With the latest reforms, GST might finally become a 'good and simple tax'

The decisions taken by the Goods and Services Tax (GST) Council in its 57th meeting on Thursday reveal two distinct changes in the attitude of the tax administration: increased trust in the taxpayer, and reduced anxiety over tax revenues. This is a big change from the system in place so far, where taxpayers have been bogged down by compliance requirements, and the tax enforcement has used this complexity to try to extract every rupee it can. The data show gross collections have not often deviated significantly from the mean over the last two years. After nine years, taxpayers have also become familiar, if not comfortable, with the tax filing system. The previous meeting also rectified most rate-related issues in GST and even reduced the number of slabs, a major driver of the complexity of the tax system. The time was ripe for a significant overhaul of the processes and administration of GST, and the Council has delivered. Thursday's reforms address complications in the entire chain of GST paperwork, from registration and return filing, to refunds and litigation. The thrust is to reduce human discretion in these processes by automating registrations, reducing the number of times small businesses have to file returns, handling refunds through computer-based verification, and significantly reducing the powers of GST officers. In essence, trust the taxpayer to comply, and crack down only when non-compliance is demonstrable. That is the way it should be, instead of a 'guilty until proven innocent' approach.

While all the simplification measures are welcome, some specific ones deserve special mention as they will substantially ease areas of major discontent. So far, taxpayers were denied input tax credits (ITC) until their suppliers had filed their returns. This meant that thousands of genuine businesses that had received supplies and paid taxes on them were denied ITC, leading to a drying up of crucial working capital. The GST Council has tasked a committee to find a solution that can be implemented by April 1. Removing the arrest powers of GST officers is another step that will significantly reduce harassment, as will tightening the rules around inspection, searches, and seizures of consignments. The Centre has also used this opportunity to introduce a faceless assessment system for Central GST registered companies, along the lines of the popular faceless system in income tax. The decision to review rates only once a year, and implement rate changes only at the start of financial years, removes significant uncertainty that usually arises each time the Council meets. In its 10th year, GST is finally starting to look like what it should have at the time of rollout.



महत्वपूर्ण तथ्य



- 57वीं GST काउंसिल बैठक (8 अक्टूबर 2026) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कई बड़े और ऐतिहासिक नीतिगत फैसले लिए गए हैं। इस बैठक का मुख्य ध्यान टैक्स दरों में बदलाव के बजाय अनुपालन (Compliance) को आसान बनाने, गैर-अपराधीकरण (Decriminalisation), और ऑटोमेशन पर रहा।

- बैठक में किए गए प्रमुख बदलाव और सिफारिशें नीचे सूचीबद्ध हैं:

1. दंडात्मक शक्तियों और अभियोजन में बड़ी राहत (Decriminalisation)

- गिरफ्तारी की शक्तियां खत्म (Arrest Powers Scrapped): GST अधिकारियों से करदाताओं को गिरफ्तार करने की शक्तियां (Section 69) वापस लेने की सिफारिश की गई है।
- प्रोसीक्यूशन लिमिट में बढ़ोतरी: GST मामलों में कोर्ट कार्यवाही (Prosecution) शुरू करने की न्यूनतम सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दी गई है।
- सामान्य जुर्माना घटाया: किसी विशिष्ट श्रेणी में न आने वाले उल्लंघनों के लिए सामान्य जुर्माना (General Penalty) ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 कर दिया गया है।

2. इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के नियमों का उदारीकरण

- कर्मचारी बीमा पर ITC: कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए खरीदी गई हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर अब ITC मिलेगा।
- इंफ्रास्ट्रक्चर पर राहत: टेलीकॉम टावर (Telecom Towers) और कारखाने से बाहर बिछाई गई पाइपलाइनों पर भी ITC क्लेम करने की छूट दी गई है।
- सैंपल और एक्सपायर्ड स्टॉक: फ्री सैंपल और कानूनी कारणों से नष्ट किए गए एक्सपायर्ड स्टॉक पर अब ITC नुकसान नहीं होगा।
- ईमानदार खरीदारों की सुरक्षा: सप्लायर द्वारा टैक्स न जमा करने पर खरीदार का ITC रोकने की समस्या की समीक्षा के लिए अधिकारियों की एक विशेष समिति बनाई गई है, जो 3 महीने में रिपोर्ट देगी।

3. छोटे कारोबारियों और MSMEs के लिए सरलीकरण

- वर्ष में केवल एक रिटर्न: ₹5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले B2C कारोबारियों के लिए 'वार्षिक रिटर्न योजना' का सिद्धांत रूप से अनुमोदन किया गया है, जिसमें वे साल में 1 रिटर्न भरेंगे और टैक्स तिमाही आधार पर देंगे।
- ₹10,000 से कम के नोटिस बंद: ₹10,000 से कम के टैक्स मामलों में कोई शो-काउज नोटिस (Show-Cause Notice) जारी नहीं किया जाएगा।
- ई-कॉमर्स विक्रेताओं को राहत: छोटे ऑनलाइन विक्रेताओं को दूसरे राज्यों में अलग से भौतिक कार्यालय (Physical Office) खोलने की आवश्यकता नहीं होगी; वे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के वेयरहाउस को मुख्य स्थान बना सकेंगे।

4. रिफंड और माल परिवहन में तेजी

- फास्ट-ट्रैक रिफंड: रिफंड क्लेम की पावती समय सीमा 15 दिन से घटाकर 10 दिन की गई है। 90% पात्र रिफंड ऑटोमैटिक जोखिम मूल्यांकन के बाद 3 कार्य दिवसों के भीतर मंजूर कर दिए जाएंगे।
- ई-वे बिल और लॉजिस्टिक्स सुधार: रास्ते में माल की भौतिक जांच (Physical Check) अब केवल ठोस खुफिया जानकारी के आधार पर और केवल मूल राज्य (Origin) या गंतव्य राज्य (Destination) के अधिकारी ही कर सकेंगे, जिससे इंटर-स्टेट माल परिवहन आसान होगा।

5. GST दरों में कोई बदलाव नहीं (No Rate Changes)

- काउंसिल ने इस बैठक में GST की टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।
- भविष्य में GST दरों से जुड़े मामलों पर विचार करने के लिए वर्ष में केवल एक विशेष बैठक समर्पित की जाएगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

YouTube Homework

➤ Government Initiatives For Skill Development

कोशल विकास के लिए
केन्द्र सरकार
की योजनाएं

India's 'WorldSkills' medals reflect patient investment

The Bhagavad Gita, in verse 18-46, says *sva-karmāṇaṁ tam abhyārcchya siddhiṁ vindati manavaḥ* – a person attains perfection by worshipping through their own work. This implies that a workbench, a kitchen or a workshop floor can be a place of devotion, and a craft practised with care is a virtue in itself, not merely a means of livelihood. Prime Minister Narendra Modi recently met India's medal winners at the 48th WorldSkills Competition, which was held in Shanghai, China (September 2026). These champions included bakers, welders, dental technicians, car painters and retail professionals. Their achievements placed India among the world's top 10 for the first time. By welcoming them, the Prime Minister has nudged Indian families to look again at skilling, a path that deserves the same honour as any other.



Jyoti Chaudhary
Minister of State
(Independent Charge)
for Skill Development
and
Entrepreneurship,
and Minister of State
for Education,
Government of India

Skilled talent on world stage

Held every two years, WorldSkills is the Olympics of skills. More than 1,400 young people from about 70 countries and regions complete practical tasks, set and judged by international experts, in trades from welding and wiring to robotics and cyber security. Indian families know the podiums of education well – toppers' lists, merit ranks and classroom gold medals. Skilling has had no such place in Indian public life. These winners are changing that. As their numbers grow, more families will recognise that skill-based careers are no less worthy and that a podium earned at the workbench stands as tall as one earned in the examination hall.

India's WorldSkills story began in a humble way and has climbed steadily. India was placed 39th in 2011 and 19th in 2017. It reached the 13th spot in 2019 and held that place in 2024, with the best results being four bronze medals. In Shanghai, India finished 10th, with six silver medals and 20 medals for excellence – 26 medals in all, and its largest haul ever. This came from India's largest team of 70 competitors across 63

कोशल
विकास

'Skill-Ex' is the investment in the people behind India's medal-winning performance at the 48th WorldSkills Competition in Shanghai, China

skills. Not only has the medal tally grown, but India's best medals have also moved from bronze to silver.

India competed in 11 skills for the first time, winning three of its six silver medals in these categories: Mohammed Salam in dental prosthetics, Kovid Gangrade in digital interactive media design and Saniya Joshi in retail sales. Smriti Nambiar bagged silver in bakery, alongside Parth Vohra in industrial design technology and Mehruissa Begum in logistics and freight forwarding.

Humble beginnings to excellence

Behind these numbers are young people whose journeys began in very ordinary places. Kaif Khan of Lucknow, Uttar Pradesh, learnt his craft while working in a private car company's workshop after class 10. He won gold in the State, regional and national rounds of IndiaSkills, trained with Maruti Suzuki and Axalta, and gained exposure in Germany and Denmark, before he earned a Medallion for Excellence in Car Painting in Shanghai. From the south, Mohammed Salam of Cuddalore, Tamil Nadu, won silver in dental prosthetics, a discipline judged on how precisely a crown or bridge fits, and one in which India had never competed before. All they needed was a fair test, comprehensive training, and an ecosystem that considered their skill seriously.

Kaif Khan, Mohammed Salam, Saniya Joshi, Smriti Nambiar and their teammates did not reach Shanghai by chance. They are the fruits of a patient investment in people. Medallions for Excellence also went to Md. Seraj in automobile technology, Pavan Bhadravati Suresha in additive manufacturing, Mallinath and Suhan Mascarenhas in Industry 4.0, and Abhishek Somanna Shignalli and Vinay Muttayya Hiremath in robot systems integration.

All of them climbed a ladder that begins in the districts and rises through State and regional rounds to the national finals. More than 3.65 lakh

young people registered for IndiaSkills across 63 skills in this cycle. Five regional competitions narrowed the field to about 650 national finalists in Greater Noida (Uttar Pradesh), where 70 were chosen to represent India. A team from the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, the National Skill Development Corporation and the States, working with industry experts, has toiled to find, hone and polish these young people for the international stage. This is the whole-of-government approach at work, and marks a deeper shift.

Nations have long measured progress in Capex, the roads, ports and factories they build, and in Opex, the cost of keeping them running. India has built on both, and now adds a third discipline, Skill-Ex – deliberate investment in the people who make every asset work. The recent Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs (PM-SETU) scheme is Skill-Ex at scale. This ₹60,000 crore scheme is upgrading 1,000 government Industrial Training Institutes (ITIs) as 200 hubs and 800 spokes, with industry partners managing the clusters.

There must be a focus on 'Skill-Ex'

Industry must join this effort. A factory is only as good as the people who run it, and employers should spend on Skill-Ex as seriously as they spend on Capex and Opex. Capex gives India its assets, and Opex keeps them running; only Skill-Ex develops the manpower to keep assets productive. A nation is built not only by those who design and govern, but also by those who weld, bake, paint and wire with care. That care is a virtue, and the Gita reminds us that it is also a form of worship. If we value skilling as much as degrees, India's young people will only ask how well they can walk their path, and India's next generation will make India the skilling capital of the world.

- 48वीं वर्ल्डस्किल् प्रतियोगिता (48th WorldSkills Competition) का विवरण इस प्रकार है:
- कहाँ हुआ (स्थान): शंघाई, चीन (Shanghai, China) — यह प्रतियोगिता नेशनल एग्जिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (NECC) में आयोजित की गई थी।
- कब हुआ (तिथि): 22 सितंबर से 27 सितंबर 2026 तक।

महत्वपूर्ण तथ्य



University students call off stir over *Vande Mataram* row

The Hindu Bureau
KASARAGOD

The students of the Central University of Kerala (CUK) have temporarily called off their protest following discussions with the university Registrar on Friday. The protest was launched after five students were suspended by the proctor for protesting during a national seminar organised at the university to mark the 150th anniversary of *Vande Mataram*.

Student representatives said the university had agreed to form an inquiry committee to examine their grievances and had accepted their demand to exclude proctor Sreekumar from the panel.



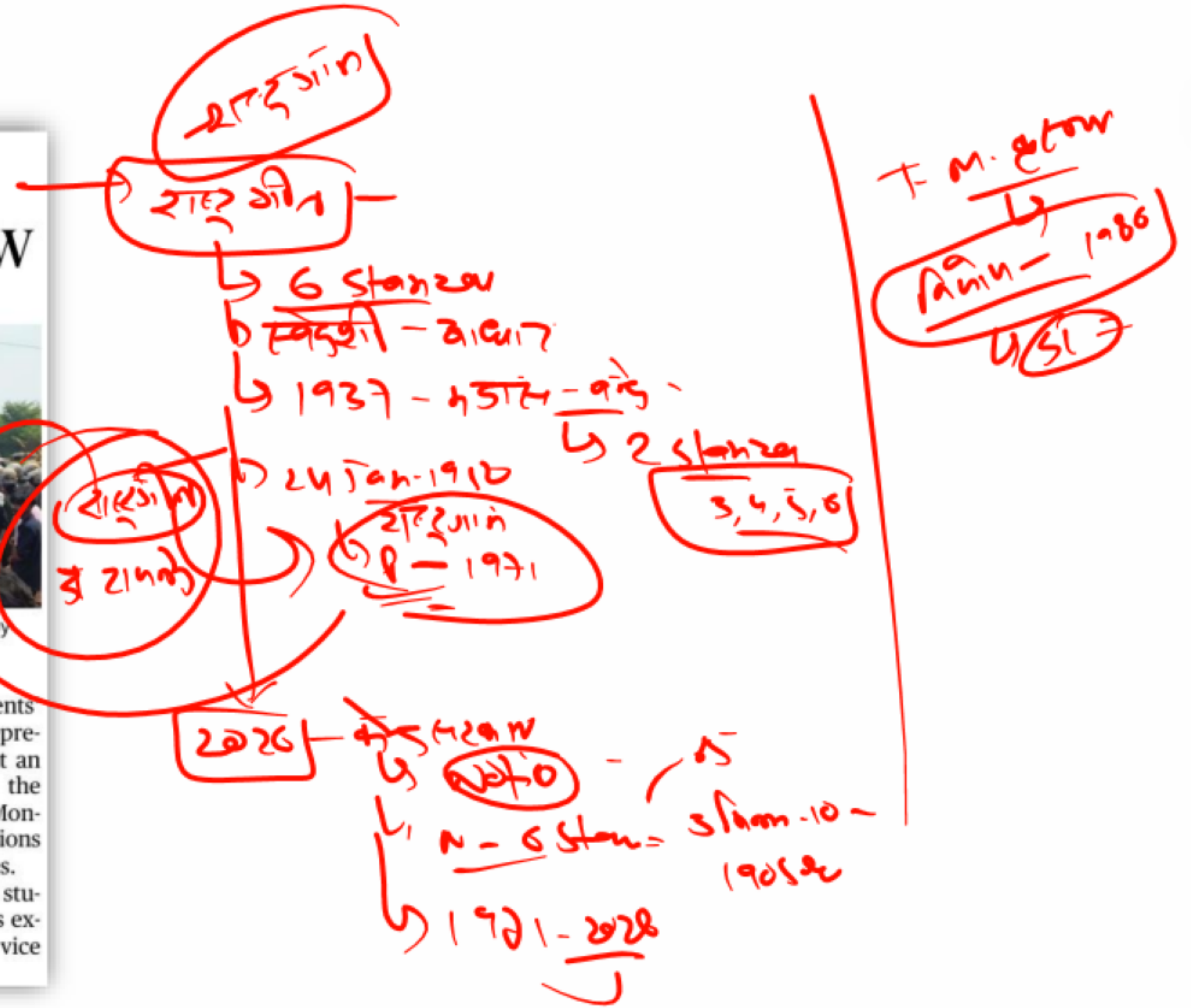
The protest was launched after five students were suspended by proctor Sreekumar. SPECIAL ARRANGEMENT

The students protested demanding, among other things, that the suspension orders be withdrawn.

During discussions with the Registrar, students insisted that they will not accept an inquiry conducted by a panel that included the proctor. However, no final decision has been

reached on the students demands. Student representatives have sought an appointment with the Vice-Chancellor on Monday to discuss suspensions and other related issues.

A delegation of five student representatives is expected to meet the vice chancellor.



महत्वपूर्ण तथ्य



India's share of global greenfield investments more than double China's during 2020-25

A report by the UN Conference on Trade and Development says greenfield investments are increasingly taking place in strategic sectors. It added that India remains the fastest-growing major economy, even though domestic consumption is starting to show signs of strain due to higher prices

T.C.A. Sharad Raghavan
NEW DELHI

India's share in global greenfield investments during 2020-25, at 5.7%, is more than double China's share in such investments during the same period, according to the latest report by the UN Conference on Trade and Development (UNCTAD).

However, it also said investment in strategic sectors still remains concentrated in Europe and North America, highlighting the integration challenges for the Global South.

The latest Trade and Development Report 2026 report by UNCTAD, released on Friday, said that greenfield investments were increasingly being made in strategic sectors. Greenfield investments refer to those made by companies in new ventures in another country.

Strategic investments

According to the data in the report, India accounted for 5.7% of global greenfield investments during 2020 to 2025, followed by Malaysia (4%), Indonesia (3.8%), and China (2.8%).

"From 2020 to 2025,



Lion's share: Among these strategic sectors, AI infrastructure and related technologies attracted the largest share. REUTERS

strategic sectors grew from 10% to 14% of global greenfield investment, which captures both their rapid progression and current importance," UNCTAD said in the report. Among these strategic sectors, artificial intelligence (AI) infrastructure and related technologies attracted the largest share

of 12.4% of the \$845.7 billion of overall global greenfield investment that took place within this period. AI infrastructure was followed by the semiconductor value chain (8.1%) and energy transition technologies and services (7.8%).

"The geographic disparity in strategic investment underscores the growing integration challenges for the Global South, especially for the least developed countries," the UNCTAD report said.

It pointed out that Europe accounted for 28.4% of strategic investment and North America captured

another 28%.

"Even among developing economies, capital is primarily funnelled into developing Asia (26.5%), with China, India, Indonesia, Malaysia and Singapore as leading jurisdictions for new investments," the report said.

The report also shows that India ranks high in terms of the number of industrial policies it has implemented over the last two decades or so. During 2008-21, India implemented 1,416 industrial policies, behind only China (4,201) and the U.S. (4,025).

YouTube Homework

UNCTAD

4.14m
3.2m
3.2m

UN-
UNCTAD
Confusion animal
Dank
Greenfield investment
GIF
ISF

UNCTAD → CFI -
India - 5.7%
Malaysia 4%
Indonesia 3.8%
China 2.8%
Strategic

महत्वपूर्ण तथ्य



IN BRIEF



RBI raises daily cash reserve ratio requirement for banks

The Reserve Bank of India (RBI) on Friday said banks will need to maintain 99% of the required cash reserve ratio (CRR) daily starting October 16, up from 90% at present. The move follows a review of the current liquidity condition in the banking system and will help reduce the banking system liquidity, which stood at a surplus of around ₹3.88 lakh crore as of October 8. PTI

- RBI - MPC
- Neutral to Calibrated Tightening
- RR - 5.50
- SDF - 5.25 ✓
- MSF - 5.75 ✓
- Bank Rate - 5.75 ✓
- CRR - 3% ✓
- SLR - 18% ✓
- GDP Growth Rate - 7.1
- Inflation - CPI - 5.2
- Core Inflation - 4.4

MPC - 47-48
Main
Liquidity

CRR

100 - 3%
NOTL
3%

RBI
CRR

only
main
914 days

90% → 99%
3.88 - 90%
3.88 - 99%

99%

1. नगद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio - CRR) क्या है?

- नगद आरक्षित अनुपात (CRR) बैंकों की कुल जमा पूंजी (Net Demand and Time Liabilities - NDTL) का वह प्रतिशत होता है जिसे बैंकों को अनिवार्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास नकदी (Cash) के रूप में रखना पड़ता है।
- मुख्य उद्देश्य: इसका उद्देश्य बैंकों में तरलता (Liquidity) का संतुलन बनाए रखना और जमाकर्ताओं के पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है।
- ब्याज: CRR के रूप में RBI के पास रखे गए पैसे पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता है।

2. Daily Maintenance को 90% से बढ़ाकर 99% करने का क्या मतलब है?

- यहाँ यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ओवरऑल CRR दर (जैसे 3% या 4.5%) में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि दैनिक रख-रखाव (Daily Maintenance) के नियम को सख्त किया गया है।
- नियम का पखवाड़ा (Fortnight) चक्र: बैंकों को RBI द्वारा निर्धारित CRR औसतन 14 दिनों (एक पखवाड़े) की अवधि में मेंटेन करना होता है।

- पहले का नियम (90%): यदि किसी बैंक को RBI के पास औसतन ₹100 करोड़ रखना अनिवार्य था, तो बैंक को छूट थी कि वह किसी एक दिन कम से कम ₹90 करोड़ (90%) रख सकता था, बशर्ते पखवाड़े के अंत में औसत ₹100 करोड़ पूरा हो जाए। इससे बैंकों को दैनिक आधार पर फंड मैनेजमेंट में 10% की छूट या लचीलापन (Flexibility) मिलता था।
- नया नियम (99%): अब बैंकों को रोज तय CRR राशि का कम से कम 99% (यानी ₹99 करोड़) हर दिन RBI के पास बनाए रखना होगा। यानी daily basis पर फंड कम रखने की सीमा को बहुत सीमित कर दिया गया है।

3. इसका अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- A. बैंकिंग प्रणाली में तरलता (Liquidity Management) पर प्रभाव
- अधिशेष तरलता (Surplus Liquidity) पर नियंत्रण: हाल के दिनों में बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त नकदी की स्थिति बनी हुई थी। RBI इस कड़े नियम के जरिए सिस्टम से अतिरिक्त नकदी के उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना चाहता है।

B. बैंकों पर प्रभाव

- **दैनिक लचीलेपन (Flexibility) में कमी:** बैंकों के पास अब रोजमर्रा के नकदी प्रबंधन (Cash Management) में बहुत कम गुंजाइश बचेगी। उन्हें daily basis पर बहुत सावधानीपूर्वक फंड मैनेज करना होगा।
- **कॉल मनी मार्केट (Call Money Market) में मांग:** जिन बैंकों के पास किसी दिन नकदी की थोड़ी भी कमी होगी, उन्हें तुरंत इंटर-बैंक ओवरनाइट मार्केट (Call Money) से उधार लेना पड़ेगा, जिससे ओवरनाइट उधारी दरों (Call Rates) में स्थिरता आएगी।

C. आम ग्राहकों / उधारकर्ताओं पर प्रभाव

- **लोन और ब्याज दरों पर प्रत्यक्ष असर नहीं:** इस फैसले से आम जनता के लिए लोन महंगे या सस्ते होने का कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक का मूल CRR प्रतिशत वही है। यह केवल बैंकों के अंतर-बैंकिंग दैनिक नकदी प्रबंधन से जुड़ा हुआ कदम है।

Govt. slams J.D. Vance over his 'indentured servants' remark

Ministry reminds Trump administration that U.S. is 'shaped by generations of immigrants', following Vance's comment on IT professionals; economic ties between the two countries may see more strain

Suhasini Haidar
NEW DELHI

The Ministry of External Affairs on Friday slammed as "unwarranted" and "deeply offensive" U.S. Vice President J.D. Vance's comments in which he called foreign workers, including Indian IT professionals, "indentured servants".

Hitting out at the U.S. government for its decision to suspend "labour certifications" from several Indian technology firms based in America, the Ministry said the steps would not "advance the shared ambitions of both countries", indicating further trouble in the already difficult economic relationship between the two countries.

On Thursday, Mr. Vance and U.S. Labour Secretary Keith Sonderling announced the suspension of the Permanent Labour Certification (PERM) programme for eight IT outsourcing giants, including five Indian IT multinationals operating in the U.S., and accused them of visa fraud. The list included In-

Such descriptions are unwarranted and ignore the fact that Indian professionals in the United States are highly educated and skilled contributors to its economy and innovation ecosystem

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

fosys, Tata Consultancy Services, Wipro, Cognizant, and HCL from India, often called the Big 5, as well as Capgemini, Microsoft, and Adobe.

"Such descriptions are unwarranted and ignore the fact that Indian professionals in the United States are highly educated and skilled contributors to its economy and innovation ecosystem," the Ministry said in a strongly worded statement that reminded the Trump administration that the U.S. had been "shaped by generations of immigrants."

"Resorting to terminology that carries painful historical and colonial legacy connotations is deeply offensive," the Ministry added, pointing to the use of indentured labour by

American and European colonial settlers in the 19th century, including in the U.S. and nearby islands to work on their farms.

'Pernicious system'

The PERM programme allows companies to certify professionals who are not U.S. citizens for essential skills, qualifying them to be sponsored for a Green Card of Permanent Residency status in the country. The U.S. government said this process benefitted more than 2,30,000 H1B visa approvals and 1,00,000 permanent residencies since 2009, claiming that the eight companies had brought in hundreds of thousands of foreign workers at lower wages through a "pernicious system" that "de-

frauded the American worker". About 70% of all H1B visa holders are Indian.

"You [the Companies] bring in indentured servants from outside the country. You lay off American workers. And if you're a corporation, you make a ton of money by undercutting the wages of American workers, replacing them with people who frankly shouldn't be in the United States of America to begin with," Mr. Vance said.

The PERM programme enables a company to sponsor a foreign employee for permanent residence in the U.S., and it must prove to the Labour Department that it tried and failed to find a comparatively qualified American for the job.

Mr. Vance's announcement came when economic ties between India and the U.S. were under strain over the lack of progress in the Free Trade Agreement talks, despite months of negotiations in Delhi and Washington and calls between Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump.

YouTube Homework

➤ H1B Visa

➤ PERM – Permanent Labour

Certification Program (Green Card)

I.P.
International Relations
II

America
Donald Trump

J.D. Vance

Green Card

IT firm

Software

8

5 + 3 = 8

YouTube Homework

A hand-drawn diagram in red ink on a white background. At the top left, 'WSA Asia' is written with an arrow pointing down. Below it, 'Mecca' is written above a box containing 'PIT'. To the right, 'Houthi' is written above 'SA', which is above 'Houthis', which is above 'Hizb'. A large oval encircles 'PIT', 'SA', and 'Houthis'. To the right of this oval, 'Kashmir' is written inside an oval. Further right, 'Harmon' is written with two horizontal lines underneath. At the top right, 'Axis of Resistance' is written in bold black text with a black arrow pointing towards it from the left. A large red arrow curves from the bottom left towards the top right, passing through the central elements of the diagram.

Two million in Gaza face a grim winter without shelters: UN

Agence France-Presse
GENEVA

Virtually all of Gaza's two million population will go through winter without adequate shelter as the Palestinian territory enters a fourth year under heavy Israeli war restrictions, the United Nations said on Friday.

The International Organisation for Migration (IOM) said nearly 1.8 million people in the territory "are facing a fourth winter without adequate protection from rain, flooding and cold".

The UN agency called for international funding for humanitarian aid and for Israel to ease the "con-



Tents sheltering displaced people in Gaza City. AP

straints" on the entry of critical supplies.

More than half of all the tents and makeshift shelters are in poor condition and should be replaced, the IOM said. "With few alternatives available, many families are living in war-damaged buildings that pose serious risks to life."

UN

महत्वपूर्ण तथ्य



YouTube Homework

International jurist Navi Pillay wins Nobel peace prize

Associated Press
OSLO

Navi Pillay, a South African-born jurist and former UN human rights chief, won the Nobel Peace Prize on Friday for her efforts to promote international law as it comes under attack.

Her win is sure to be seen as a high-profile rebuke to U.S. President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who have both rejected the findings of the UN commission she led in Gaza.

On the 125th anniversary of the prize's inception, the Norwegian Nobel Committee sought "to remind the world that the rule of law, national and international, underpins the system we have set up to



A voice for human rights

Born to parents of Tamil descent under apartheid in South Africa, Navi Pillay rose to become a prominent jurist and advocate of international law and human rights

- Challenged discrimination, segregation, and exclusion in apartheid-era South Africa
- Led the UN's human rights office as High Commissioner and chaired its inquiry into the Occupied Palestinian Territory
- Held judicial posts in South Africa's High Court, the Rwanda
- Currently serves as a judge at the International Court of Justice in the genocide case against Myanmar

ensure peace and resolve conflicts nonviolently. Peace requires justice, committee Chairman Jørgen Watne Frydnes said.

Judges "guard the thin red line between order and chaos," and the world needs jurists "of courage, vision and determination."

qualities that Navi Pillay demonstrates in her work on the bench".

In places such as Israel and in apartheid-era South Africa, she and peers took on some of the world's most painful and sensitive legal issues and most vulnerable populations.

Ms. Pillay, 85, received the news while attending a forum in Nuremberg, Germany, where the trials of Nazi war criminals helped lay the foundations of international law.

She said efforts to weaken international criminal justice "endanger the progress painstakingly made since Nuremberg, and they risk returning us to a world in which power, rather than law, determines whose suffering matters."

Ms. Pillay chaired the Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory and Israel, which was created by the UN-backed Human Rights Council. The commission a year ago concluded Israel was responsible for genocide in Gaza with a specific intent to destroy Palesti-

nians in Gaza.

Gaza was among Ms. Pillay's first comments on Friday after hearing she had won. "What's happening there is genocide," she said.

The commission last year also found that the Israeli President, Prime Minister and former Defense Minister "have incited the commission of genocide." Israel has strenuously denied the accusations.

Ms. Pillay has repeatedly rebuffed critics who accused her of antisemitism or turning a blind eye to the Hamas attacks in Israel. Under her leadership, the commission also issued reports accusing Hamas of war crimes and violations of international humanitarian law during its October 7, 2023, attack.

- Medicine
- Physics
- Chemistry
- Literature

महत्वपूर्ण तथ्य



813

रक्षा मंत्रालय



SIDM Champion Award

रक्षा क्षेत्र

रक्षा मंत्री ने एसआईडीएम चैंपियन पुरस्कार 2026 प्रदान किए तथा रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ देश की रक्षा उत्पादन क्षमता को और सशक्त करने का आह्वान किया

“राष्ट्रीय सुरक्षा अब तेजी से इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे पास देश में ही अपनी रक्षा सेनाओं के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी व उपकरणों को डिजाइन करने, विकसित करने, निर्मित करने और उन पर नियंत्रण रखने की कितनी क्षमता है।” — श्री राजनाथ सिंह

“भारत का रक्षा निर्यात एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।” — रक्षा मंत्री

“रक्षा उपकरण निर्माताओं को अनुसंधान एवं विकास पर होने वाले खर्च को ऐसे निवेश के रूप में देखना चाहिए, जो परिचालन तैयारियों को मजबूत करता है, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देता है।” — श्री राजनाथ सिंह

महत्वपूर्ण तथ्य



YouTube Homework



संचार मंत्रालय

भारत 6G एलायंस ने तीसरे अंतरराष्ट्रीय भारत 6G संगोष्ठी 2026 में वैश्विक साझेदारी मजबूत की

संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी ने समापन सत्र को संबोधित किया; दूरसंचार विभाग ने ESTIC 2026 और इंटेलिजेंट नेटवर्क व क्वांटम कम्युनिकेशन पर बल की जानकारी दी

प्रविष्टि तिथि: 09 OCT 2026 7:41PM by PIB Delhi

नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में तीसरे अंतरराष्ट्रीय भारत 6G संगोष्ठी 2026 का समापन हुआ। समापन सत्र को संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी ने संबोधित किया। भारत 6G एलायंस (B6GA) द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के साथ आयोजित इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में ग्लोबल टेलीकॉम लीडर्स, नीति-निर्माता, मानक संगठन, उद्योग जगत, शिक्षाविद और शोधकर्ता एक साथ आए ताकि IMT-2030 और उससे आगे की रूपरेखा पर चर्चा की जा सके।



ESTIC-2026
संचार

Bharat 6G Alliance

India Mobile Congress-2026
Bharat 6G Alliance

महत्वपूर्ण तथ्य



रक्षा मंत्रालय



भारतीय नौसेना अपने स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत 'मंगरोल' को बेड़े में शामिल करेगी

प्रविष्टि तिथि: 09 OCT 2026 7:13PM by PIB Delhi

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) कोच्चि द्वारा निर्मित तीसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शैलो वॉटर क्राफ्ट (एसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी) 'मंगरोल' 12 अक्टूबर 2026 को नौसेना डॉकयार्ड, मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता पाश्चिमी नासना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन करेंगे। इस अवसर पर नौसेना और रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा मंत्रालय एवं कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के प्रतिनिधि, पूर्व सैनिक तथा स्वदेशी हथियारों और सेंसर निर्माताओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक तटीय शहर और प्रमुख मछली पकड़ने के बंदरगाह 'मंगरोल' के नाम पर नामांकित यह पोत, पूर्ववर्ती आईएनएस मंगरोल (एम 85) की विरासत को आगे बढ़ाता है, जो एक सुरंगरोधी पोत था और जिसने 07 अप्रैल 2004 तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दी थीं। इस पोत का नामकरण अपने पूर्व युद्धपोतों की विरासत को संजोकर रखने की नौसेना की परंपरा को बनाए रखता है।

80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री से बना 'मंगरोल' युद्धपोत के डिज़ाइन, निर्माण और उन्नत हथियारों व सेंसर को जोड़ने के मामले में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दिखाता है। भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) द्वारा बनाया गया यह जहाज़, रक्षा क्षेत्र में जहाज़ बनाने के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और अहम कदम है।

Home Assignment



- ☐ Article 22
- ☐ Human Rights Day

प्रश्न: बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य (Bab-el-Mandeb Strait), जो लाल सागर (Red Sea) को अदन की खाड़ी (Gulf of Aden) से जोड़ता है, के दोनों किनारों पर स्थित प्रमुख देश निम्नलिखित में से कौन-से हैं?

- (a) मिस्र (Egypt) और सूडान (Sudan)
- (b) यमन (Yemen) और जिबूती (Djibouti)
- (c) सऊदी अरब (Saudi Arabia) और इरिट्रिया (Eritrea)
- (d) ओमान (Oman) और सोमालिया (Somalia)

Thanks For Watching

Follow us for more Updates



@RRESULTMITRAOFFICIAL



Join our Telegram



@SUNILVERMA_THEIASMENTOR



Follow on Instagram



Subscribe Now

Stay Connected

Learn
Share
Grow
Together ♥

Better
Students
Brighter
Tomorrow

Small
Steps
Big
Results
😊

DISCIPLINE
CONSISTENCY
SUCCESS